गाड़ी से है जिसे परीक्षण के तौर पर 26-2-1977 से भागलपुर तक बढ़ाया गया था लेकिन कम उपयोग किये जाने के कारण 1-10-77 इसका चालन क्षेत्र घटाकर भागलपुर-साहिबगंज के बीच कर लिया गया है । अब तक केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : निम्नलिखित जोड़ी के गाड़ियों में स्थानों का उपयोग इस प्रकार होता है:—

333 अप 30 प्रतिशत

334 डाउन 36 प्रतिशत

समय-सारणी में परिवर्तन करके इसे लाभ दायक बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह केवल हावड़ा-साहिबगंज यात्री गाड़ी के चालन क्षेत्र का विस्तार था । टिकट चेकिंग का काम एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे लाभप्रदता पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । गाड़ी-वार लाभ और हानि का विवरण उपलब्ध नहीं है । कम उपयोग किये जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था ।

कोरबा, रांची, दाली तथा राजहारा को मिलाती हुई नई रेलवे लाइन

267. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा, रांची, दाली तथा राजहारा को मिलाती हुई एक रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). कोरबा को रांची के साथ रेल लाइन द्वारा जोड़ने के लिए, जिसकी लम्बाई 312 कि०मी० है, एक यातायात सर्वेक्षण किया गया है । संसाधनों की कमी के कारण इस समय इस परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

Proposals to improve Legal Procedures

268. SHRI KACHARU LAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the question to improve the legal procedures and thereby make the system of justice quick and inexpensive has been engaging the attention of the Government for some time past;

(b) if so, whether any decision has since been taken in the matter;

(c) if so, the sailent features thereof; and

(d) if not, the reasons for delay in taking a decision soon on such a vital issue and when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Law Commission of India in its Fourteenth Report on the Reform of Judicial Administration had made several recommendations for improvement of the legal procedures and to make the system of justice quick and inexpensive. As the administration of justice was, until the enactment of the Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976, a State subject, these recommendations were sent to the State Governments for implementation.

Apart from this, the Central Government has taken several steps to